

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 618
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अकोले नगर पंचायत को निधि

618. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी तालुका अकोले नगर पंचायत को पिछले एक वर्ष से जल संकट, कचरा निपटान के लिए अतिरिक्त मशीनरी खरीदने के लिए धन का संकट, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायत को धन आवंटित नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त सभी कार्यों के लिए शिरडी संसदीय क्षेत्र में स्थित आदिवासी अकोले नगर पंचायत को 15वें वित्त आयोग के माध्यम से धन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 15वें वित्त आयोग (15वें एफसी) ने अन्य बातों के साथ-साथ दस लाख से कम आबादी वाले शहरों (एनएमपीसी) को टाइड और अनटाइड अनुदानों के रूप में अनुदान की सिफारिश की है।

टाइड अनुदान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) सहित जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार करने के लिए नियत है, जो जन स्वास्थ्य का हिस्सा हैं, जिसमें एसडब्ल्यूएम सहित जल

आपूर्ति और स्वच्छता को 50:50 का आवंटन है। अनटाइड अनुदान एनएमपीसी द्वारा संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 विषयों के भीतर उनकी मूल्यांकित आवश्यकताओं के आधार पर उपयोग करना है, जिसमें जल और स्वच्छता शामिल हैं।

15वें वित्त आयोग का अनुदान राज्य सरकार को एक वित्तीय वर्ष के लिए दो बराबर किस्तों में वितरित किया जाता है, जो बाद में उन्हें जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में या नवीनतम राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार एनएमपीसी को आवंटित करता है।

महाराष्ट्र के लिए वित्त वर्ष 2023-24 की पहली किस्त तक के टाइड और अनटाइड अनुदान संवितरित किए जा चुके हैं। एनएमपीसी के लिए टाइड और अनटाइड अनुदान के लिए 2023-24 की दूसरी किस्त के लिए दावा राज्य से प्रतीक्षित है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनपीएमसी अनुदान की दूसरी किस्त के लिए अकोले नगर पंचायत के लिए किसी भी जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।
